भारत बनेगा दुनिया का दूसरा सोलर बाजार

2026 में भारत की सौर क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक रहने का अनुमान

मुंबई, 14 जनवरी. भारत का सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण बाजार 2026 में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बाजार बन जाएगा. वैश्विक जिंस बाजार अनुसंधान फर्म ब्लूमबर्ग एनईएफ की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी .

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण की वर्तमान गति से 2030 तक पांच लाख मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लगता है लेकिन 2024 में नीलाम कई परियोजनाओं को अब भी बिजली के खरीदारों का इंतजार है जो लक्ष्य की राह में एक जोखिम है. इसमें सौर ऊर्जा मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से अधिक हो चुकी है. इसके साथ ही इनके निर्माण में कुछ कच्चे माल और हिस्से पुर्जों के लिए आयात निर्भरता बनी हुई है.

बीएनईएफ की ओर से मीडिया को उपलब्ध करायी गयी इस रिपोर्ट के सारांश में कहा गया है कि इस वर्ष चीन की धीमी गति पड़ेगी और इससे पहली बार वैश्विक सोलर निर्माण में कुल मिला कर कमी होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सौर निर्माण बाजार में तेज गिरावट दिख रही है और 2026 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर बाजार बनने के लिए तैयार है. अमेरिका में गिरावट के बीच सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में नाम मात्र की वृद्धि जारी है .

> भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का नीलामी कार्यक्रम इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को मजबूत आधार दे रहा है. रिपोर्ट में जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 60,000 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमताओं वाली परियोजनाएं नीलाम कीं. इनमें से 42,000 मेगावाट की परियोजनाएं बिजली खरीद के पक्के अनुबंधों की प्रतीक्षा में हैं .इनका भविष्य इन प्रस्तावित अनुबंधों पर टिका है. इसमें 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के समग्र लक्ष्य को पूरा करने में जोखिम भी छुपा है.

उतार-चढ़ाव में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर

नई दिल्ली, 14 जनवरी. विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को उतार-चढ़ाव देखा गया और प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 244.98 अंक (0.29 प्रतिशत) गिरकर 83,382.71 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 66.70 अंक यानी 0.26 प्रतिशत उतरकर 25,665.60 अंक पर रहा. यह दोनों सूचकांकों का 07 नवंबर 2025 के बाद का निचला स्तर है. इससे पहले शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव रहा. बीच कारोबार में सेंसेक्स ऊपर 83,809.98 अंक और नीचे 83,185.20 अंक तक गया. दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने लिवाली की.

सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल

1.42 लाख रुपए पार पहुंचा सोना

14 हजार रुपए बढ़ी चांदी

नई दिल्ली , 14 जनवरी. देश के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को चौंका दिया. 14 जनवरी 2026 को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा भावों के मुताबिक 24 कैरेट सोना पहली बार 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमतों में भी ऐतिहासिक तेजी देखी गई है और यह एक ही दिन में 14 हजार रुपये से ज्यादा महंगी हो गई है.

इस उछाल ने उन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जिन्होंने हाल के महीनों में कीमती धातुओं में पैसा लगाया था. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब शेयर बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सोना-चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे इनकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है. भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ने तेज छलांग लगाकर नया उत्साह पैदा कर दिया.

> इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,42,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 1,40,284 रुपये था. यानी सिर्फ 24 घंटे में सोना 1,868 रुपये महंगा हो गया. इसी तरह 23 कैरेट सोना 1,41,583 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,30,211 रुपये, 18 कैरेट सोना 1,06,614 रुपये और 14 कैरेट सोना 83,159 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. सभी कैटेगरी में एक से दो हजार रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बाजार में तेज मांग का संकेत देती है.

पीएफआरडीए ने पेंशन फंड के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

नई दिल्ली,14 जनवरी. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन निधियों के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. इसमें कहा गया है कि पेंशन निधियों का पंजीकरण दो चरणों में होगा. पहले चरण में योग्य प्रायोजक इसके लिए आवेदन करेंगे जिसके आधार पर उनका चयन किया जायेगा.

दूसरे चरण में वे उनके द्वारा प्रस्तावित पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेंगे. प्रायोजक कंपनी के लिए अपनी कुल चुकता पूंजी का कम से कम 20 प्रतिशत उस पेंशन कोष में रखना अनिवार्य होगा जिसकी स्थापना वे करेंगे. संयुक्त उपक्रम भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन शुल्क 10 लाख रुपये रखा गया है जिस पर कर तथा अन्य शुल्क अलग से देना होगा. आवेदन करने के लिए अर्हता के तहत फंड प्रबंधन में कम से कम पांच साल के अनुभव और पिछले पांच वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये के नेटवर्थ और आवेदन की तिथि पर 25 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी की अर्हता रखी गयी है. उसका रिजर्व बैंक, सेबी या भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थान होना अनिवार्य होगा. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पिछले पांच वित्त वर्ष में से कम से कम तीन में प्रायोजक को कर बाद मुनाफा हुआ हो और इस दौरान कभी भी नकदी का नुकसान न हुआ हो.

आईसीसी करार से निवेश को नई रफ्तार

सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी से बनेगा कारोबारी सुपरहाइवे

महाराष्ट्र बना निवेशकों की पहली पसंद बनने को तैयार

मुंबई,14 जनवरी. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय व्यवसायों और महाराष्ट्र राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने और परस्पर जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत निवेश सुविधा, कारोबार की आसानी और उद्योग-सरकार के बीच संवाद पर फोकस किया गया जायेगा.

एमओयू पर महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (उद्योग, निवेश और सेवाएं) पी. अनबलगन और आईसीसी के महानिदेशक डॉ. राजीव सिंह ने हस्ताक्षर किये. इस दौरान व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थीं. डॉ. अनबलगन ने कहा कि आईसीसी के साथ यह साझेदारी महाराष्ट्र के उद्योग और निवेशकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने में मददगार होगी. साथ ही एक सुविधाजनक और निवेशकों के अनुकूल महौल तैयार करने की राज्य की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी.

भारतीय व्यापार समुदाय के बीच संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करना

डॉ. सिंह ने कहा कि यह करार प्रगतिशील राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच एक पुल की तरह काम करने की आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है .इस समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और राज्य सरकार तथा भारतीय व्यापार समुदाय के बीच संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करना है . एमओयू के प्रावधानों के अनुरूप आईसीसी महाराष्ट्र में वार्षिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित करेगा, देश और विदेशों में अपने प्रमुख कार्यक्रमों में महाराष्ट्र से मंत्री और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करेगा, जो घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के राज्य के प्रयासों को प्रभावशाली तरीके से रखेंगे .

थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 0 .83 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली, 14 जनवरी. विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से दिसंबर 2025 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गयी. सितंबर 2025 के बाद तीन महीने में पहली बार थोक महंगाई की दर शून्य से ऊपर रही है. इससे पहले नवंबर में यह शून्य से 0.32 प्रतिशत नीचे थी. वहीं दिसंबर 2024 में यह 2.57 प्रतिशत रही थी. खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर गत दिसंबर में शून्य रही. यह नवंबर में शून्य से 2.6 प्रतिशत नीचे रही थी. दिसंबर में सालाना आधार पर आलू, प्याज और दालों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गयी. प्याज 54.4 प्रतिशत, आलू 38.21 प्रतिशत और दालें 13.88 प्रतिशत सस्ती हुई. सब्जियों के दाम भी 3.5 प्रतिशत घटे.

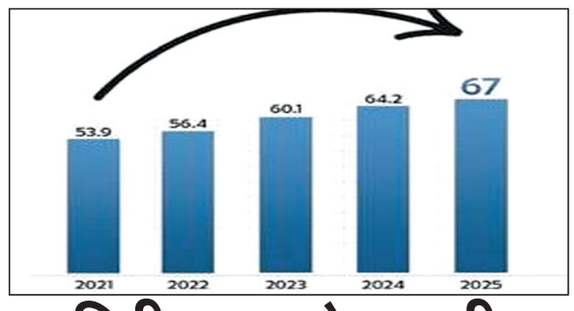

वित्तीय समावेशन की असली परीक्षा अब शुरू

सीईए नागेश्वरन का समावेशी वित्त पर बड़ा बयान

खाते नहीं, कारोबार बढ़े-तभी सफल है समावेशन

नई दिल्ली, 14 जनवरी. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि उससे वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को कितना बल और प्रोत्साहन मिल रहा है.

डॉ नागेश्वरन ने इस संबंध में रेहड़ी- खोमचे वालों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उल्लेख किया जिसने कोविड महामारी से प्रभावित दौर में लोगों को अपनी अपनी रोजी-रोटी के माध्यम को संभालने और मजबूत करने में मदद की. वह एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से यहां समावेशी वित्त पर आयोजित दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन- ग्लोबल इनक्लूसिव फाइनांस समिट 2026 के एक सत्र को संबोधित कर रहे थे.सम्मेलन के पहले दिन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज की ओर से इंडिया इनक्लूसिव फाइनांस रिपोर्ट-2025 जारी की गयी.

डॉ नागेश्वरन ने आज इस सम्मेलन में इनक्लूसिव फाइनेंस इंडिया पुरस्कार वितरण सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा, समावेशी वित्त सुविधा तभी सफल होती है जब यह आर्थिक गतिविधि को मज़बूत करती है न कि जब यह अपने आप में एक मकसद बन जाती है.

> इस सम्मेलन में विशेष रूप से इस बात पर चर्चाएं की गयी कि भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को अब आगे कर्ज सुविधाओं के विस्तार से लेकर क्षमता, विश्वास और संस्थागत शक्ति को बढ़ाने की दिशा में कैसे विकसित होना चाहिए . सम्मेलन में वित्तीय क्षेत्र के नीति निर्माताओं, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया . इस अवसर पर जारी इंडिया इनक्लूसिव फाइनेंस रिपोर्ट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है .

नागराजू ने बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा की

नई दिल्ली, 14 जनवरी. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उनके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जिसमें इन कंपनियों की लाभप्रदता, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ग्राहक-केंद्रित सुधारों पर ज़ोर दिया गया.

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार समीक्षा बैठक में श्री नागराजू ने ग्राहकों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक शिकायतों के समय पर समाधान और निर्बाध और त्वरित दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया. बैठक में कंपनियों के वर्ष 2024-25 और 2025-26 की पहले छमाही के वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा की गयी . बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल के प्रतिनिधि शामिल थे. श्री नागराजू ने ज़ोर दिया कि सावर्जनिक बीमा कंपनियों को लाभदायक व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखते हुए और अपने खुदरा पोर्टफोलियो को लगातार मज़बूत करते हुए नुकसान अनुपात को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनानी चाहिए.

वेदांता ने एक साल में दिया 56 प्रतिशत रिटर्न

नयी दिल्ली, 14 जनवरी. खनन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता के शेयरों ने पिछले एक साल में 56 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है और उसका बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 2.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी ने बुधवार को एक नोट में बताया कि कमोडिटी की कीमतों में लगातार तेजी के कारण वेदांता के शेयर बुधवार को 38.60 रुपये यानी 6.06 प्रतिशत उछलकर 675.70 रुपये पर बंद हुए. इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2,64,225 करोड़ रुपये पहुंच गया.

टीसीएस कर्मचारी की सैलरी गिरावट ने मचाया हड़कंप

मुंबई, 14 जनवरी. रेडिट पर वायरल हुई यह पोस्ट भारत के आईटी सेक्टर की उस सच्चाई को उजागर करती है, जिसे अक्सर चमकदार पैकेज और मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांड वैल्यू के पीछे छुपा दिया जाता है.

खुद को डेवलपर बताने वाले इस टीसीएस कर्मचारी ने बताया कि उसने साल 2020 में 25 हजार रुपये महीने की सैलरी पर कंपनी जॉइन की थी, लेकिन 2026 में साढ़े पांच साल बाद उसकी इन-हैंड सैलरी घटकर 22,800 रुपये रह गई है. कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में यह भी स्वीकार किया कि करियर की शुरुआत में उसने आईटी स्किल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना देना चाहिए था. वह एक टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएट था और टीसीएस जॉइन करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में ज्यादा समय लगाता रहा. इसका असर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग पर पड़ा और उसे लगातार सी और डी जैसे लो परफॉर्मेंस बैंड्स मिलते रहे.

समाचार विशेष

हॉट सीट शेखूपुर पर अखिलेश का सरप्राइज प्लान

बदायूं. अब तक दो परिवारों के बीच रहने वाली शेखूपुर विधानसभा की सीट पर सपा इस बार नए समीकरण बना रही है.

यादव मुस्लिम और मौर्य मतदाताओं की अधिकता वाली इस सीट के लिए सपा ने नई रणनीति के संकेत भी दिए हैं. हालांकि अब तक खुले तौर पर पत्ते भले न खोले हों, लेकिन जिले की राजनीति में सेक्युलर छवि रखने वाले एक पूर्व मंत्री का बार बार शेखूपुर की ओर रुख करना बता रहा है कि अंदरखाने कुछ तो खिचड़ी पक रही है. वहीं इसका एक और कारण माना जा रहा है वह यह कि हाल ही में एक जनप्रतिनिधि को हृदयरोग संबंधित समस्या आई थी जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उन्हें अब आराम करने की सलाह दी है. परिसीमन के बाद 2012 में उसहैत विधानसभा की सीट को खत्म कर शेखूपुर सीट गठित की गई थी. उसहैत विधानसभा सीट होते हुए और इसके बाद शेखूपुर सीट बन जाने के बाद पिछले चार चुनावों में यहां एक ही मुहल्ले में रहने वाले दो राजनीतिक परिवारों का दबदबा रहा.

2027 में किसे देगी टिकट समाजवादी पार्टी?

अखिलेश ने सेट किया नया फार्मूला, चुनाव से पहले चल दिया बड़ा दांव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल से अधिक का वक्त बाकी है. लेकिन सियासी दलों और सियासतदानों ने अभी से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं.

इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अंदरखाने से एक बड़ी खबर सामने आई है. जिसमें वह टिकट बंटवारे के लिए फार्मूला बदलने जा रही है. समाजवादी पार्टी टिकट देने से पहले संभावित उम्मीदवारों के सपोर्ट बेस का आकलन करेगी. इसमें जातिगत समीकरणों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल है. इसी के हिसाब से उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा. राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया जाएगा. इस सर्वे के आधार पर ही गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय किया जाएगा.

समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में मिले शानदार नतीजों को बनाए रखना चाहती है. इसलिए पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि मजबूत सपोर्ट बेस वाले नेताओं की पहचान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सर्वे किया जाएगा. इसके लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम इकट्ठा किए जा रहे हैं. सर्वे में उम्मीदवारों के अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव का आकलन किया जाएगा. इससे यह भी पता चलेगा कि क्या उम्मीदवारों की दावेदारी हर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों के हिसाब से है. जो लोग सभी मानदंडों को पूरा करेंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा.

> **दूसरी पार्टियों के मजबूत दावेदारों पर भी विचार**
>
> 2027 से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है. जिसमें वह अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ दूसरी पार्टियों के मजबूत दावेदारों पर भी विचार कर रहे हैं . सपा का मानना है कि ब्राह्मण समुदाय में किसी भी तरह की नाराज़गी का उसे फायदा मिल सकता है. जिन विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण आबादी ज़्यादा है, वहां सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनकी अपनी सीटों पर मजबूत पकड़ होगी .

जाखड़ की चुप्पी ने खड़े किए कई सवाल

जालंधर. पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गठबंधन कभी सबसे स्थिर और प्रभावी राजनीतिक प्रयोग माना जाता था. 2020 में किसान आंदोलन के बाद यह गठबंधन टूट गया लेकिन अब यह फिर से सियासी चर्चा का केंद्र बन गया है.

कुछ दिन पहले अकाली दल से गठबंधन की वकालत करने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ अब इस विषय पर खामोशी साधे हुए हैं. उनका मौन अब इस सवाल को और भी जटिल बना रहा है.

1997 से 2020 तक यह गठबंधन पंजाब की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा. 1997 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन को 117 में से 93 सीटें मिलीं. 2007 और 2012 में भी यह गठबंधन मजबूत स्थिति में रहा और क्रमशः 67 और 68 सीटों पर जीत हासिल की लेकिन 2020 में गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों को लगातार नुकसान हो रहा है. 2022 विधानसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिलीं जबकि भाजपा को दो सीटें मिलीं. 2024 लोकसभा चुनाव में अकाली दल को एक सीट और भाजपा को शून्य सीटें मिलीं.

पुराने आंकड़े गठबंधन को फायदेमंद-भाजपा की नई रणनीति के अनुसार पार्टी पंजाब में खुद को मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जाखड़ की चुप्पी दरअसल भाजपा नेतृत्व की दुविधा को दर्शाती है. एक ओर जहां पुराने आंकड़े गठबंधन को फायदेमंद बताते हैं, वहीं दूसरी ओर बदली राजनीतिक परिस्थितियों में यह जोखिम भरा हो सकता है. भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं में यह संदेश भेजा है कि जब भी अकाली दल से गठबंधन की बात होती है, तो उन नेताओं का मनोबल टूटता है जो पिछले पांच साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं.

शिअद से गठबंधन : फायदे और नुकसान

शिअद-भाजपा गठबंधन का इतिहास चुनावी दृष्टिकोण से फायदेमंद रहा है, लेकिन अब की राजनीति में यह एक जटिल सवाल बन चुका है . पुराने आंकड़े यह बताते हैं कि गठबंधन से दोनों दलों की ताकत बढ़ती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके साथ जुड़े खतरे भी कम नहीं हैं . भाजपा पंजाब में 117 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्तमान में पार्टी 43 सीटों पर मजबूत है . इस संदर्भ में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इसलिए न तो खुला समर्थन है और न ही खुला विरोध, बस एक रणनीतिक चुप्पी है

पेज एक का शेष

डबल इंजन सरकार से विकास को गति

इस तरह की अन्य योजनाएं भी हैं . उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पीएमजी और प्रगति पोर्टल से पुरानी प्रणाली को जड़ से खत्म कर असंभव दिखने वाली परियोजनाओं को साकार किया है . अब विकास के साथ आवश्यकताओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है . पीएम 'प्रगति' और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के माध्यम से मध्यप्रदेश में ऐसा ईको-सिस्टम तैयार हो चुका है, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधुनिक तकनीक के बल पर अधोसंरचना विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही हैं . डॉ. यादव ने तेलंगाना राज्य से जुड़ा प्रसंग सुनाते हुए कहा कि राज्यों के बीच राजनैतिक दृष्टि से भले ही दलों में मतभिन्नता हो, लेकिन राष्ट्र के विकास की दृष्टि से सभी राज्यों का महत्व है . 'प्रगति' पोर्टल से देश के विकास में भू-गर्भ संपदा का दोहन देशहित में अधिक प्रभावी तरीके से होगा . मुख्य सचिवजैन ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि प्रगति प्लेटफार्म की शुरूआत 25 मार्च 2015 को हुई थी . प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ अवसर पर कहा था, 'आज पूरा विश्व भारत को बड़ी उत्सुकता से देख रहा है . ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की शासन-व्यवस्था और अधिक प्रभावी, और अधिक संवेदनशील बने . इसी दिशा में 'प्रगति पोर्टल' महत्वपूर्ण कदम है .' प्रगति की 50वीं बैठक 31 दिसंबर 2025 को सम्पन्न हुई .

विशेष | **राहुल-प्रियंका का भरोसा, बढ़ी सियासी हैसियत**

कन्हैया को केरल जिताने की जिम्मेदारी

पटना. भले ही कन्हैया कुमार अब तक चुनावी राजनीति में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हों, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है.

आज की राजनीति में सफलता को केवल चुनावी जीत-हार से नहीं आंका जा सकता, बल्कि यह देखा जाता है कि किसी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर कितनी स्वीकार्यता है और वह किस हद तक विमर्श को प्रभावित कर पा रहा है. इस कसौटी पर कन्हैया कुमार निस्संदेह एक प्रभावशाली नाम बनकर उभरे हैं. कांग्रेस के भीतर और बाहर, कन्हैया को बिहार के ऐसे युवा नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय मंच पर राज्य की बात मजबूती से रख सकते हैं. मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से जिन नेताओं की चर्चा होती है, उनमें कन्हैया सबसे आगे नजर आते हैं. यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व भी उन्हें लगातार अहम जिम्मेदारियां सौंपता दिख रहा है और बड़े राजनीतिक अभियानों में उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कन्हैया बिहार के सबसे बड़े स्टेकहोल्डर की भूमिका में होंगे. इसका कारण सिर्फ उनकी वैचारिक स्पष्टता नहीं, बल्कि युवाओं, छात्रों और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता भी है. वे बेरोजगारी, शिक्षा, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं, जिससे उन्हें देशभर में पहचान मिली है. बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो लंबे समय से यह राज्य नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है. लेकिन इनके बाद वाली पीढ़ी में ऐसे नेताओं की संख्या बेहद कम है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की आवाज बन सकें. इस खालीपन को भरने की क्षमता अगर किसी में दिखती है, तो वह कन्हैया जैसे युवा नेताओं में नजर आती है.